MPSE-007 (Part-6)

Social Movement & Politics in India

(भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति)

Expected Questions & Important Topics

In both Hindi & English

Scholarly Minds

TOPIC 1

Write about human development index.

The Human Development Index (HDI) is a composite statistical measure used to assess and compare the overall development and quality of life in different countries.

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) एक समग्र सांख्यिकीय माप है जिसका उपयोग विभिन्न देशों में जीवन के समग्र विकास और गुणवत्ता का आकलन और तुलना करने के लिए किया जाता है।

It was introduced by the United Nations Development Programme (UNDP) in its first Human Development Report in 1990.

इसे 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था

The HDI aims to provide a broader understanding of development beyond just economic growth, incorporating dimensions of human well-being.

एचडीआई का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास से परे, मानव कल्याण के आयामों को शामिल करते हुए विकास की व्यापक समझ प्रदान करना है।

Here are the key aspects of the HDI:

COMPONENTS OF HDI

Health:

This is measured by life expectancy at birth, which indicates the average number of years a newborn is expected to live if current mortality rates continue.

स्वास्थ्य: यह जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है, जो इंगित करता है कि वर्तमान मृत्यु दर जारी रहने पर एक नवजात शिशु के जीवित रहने की औसत संख्या कितनी होगी।

Education:

Education is assessed through two indicators: the mean years of schooling for adults aged 25 and older, and the expected years of schooling for children entering school.

शिक्षा: शिक्षा को दो संकेतकों के माध्यम से आंका जाता है: 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष, और स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष।

Standard of Living:

This dimension is measured by Gross National Income (GNI) per capita adjusted for purchasing power parity (PPP), which reflects the average income of a country's citizens and their ability to access goods and services.

जीविका का स्तर: इस आयाम को सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) प्रति व्यक्ति द्वारा मापा जाता है, जो खरीद शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित होता है, जो किसी देश के नागरिकों की औसत आय और वस्तुओं और सेवाओं तक उनकी पहुंच को दर्शाता है।

Scholarly Minds

Topic -2

Write about working class movements in India.

Introduction to Working-Class Movements in India

The working-class movements in India have a rich history intertwined with the country's struggle for independence and its post-independence socio-economic development. These movements have played a crucial role in advocating for labor rights, better working conditions, fair wages, and social justice.

भारत में श्रमिक वर्ग आंदोलनों का एक समृद्ध इतिहास है जो देश की स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इन आंदोलनों ने श्रमिक अधिकारों, बेहतर कार्य परिस्थितियों, उचित मजदूरी और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Early Beginnings and Industrialization

The genesis of the working-class movements in India can be traced back to the late 19th century, coinciding with the advent of industrialization. The establishment of textile mills, railways, and other industries led to the formation of a new working class that began to organize itself to demand better wages and working conditions.

भारत में श्रमिक वर्ग आंदोलनों की उत्पत्ति 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई, जो औद्योगिकीकरण की शुरुआत के साथ मेल खाती है। कपड़ा मिलों, रेलवे और अन्य उद्योगों की स्थापना ने एक नए श्रमिक वर्ग को जन्म दिया जिसने बेहतर मजदूरी और कार्य परिस्थितियों की मांग करने के लिए संगठित होना शुरू किया।

Formation of Trade Unions

The formation of trade unions marked a significant milestone in the labor movement. The All India Trade Union Congress (AITUC), founded in 1920, was one of the earliest and most influential trade

Scholarly Minds

unions in the country. It played a pivotal role in uniting workers across different sectors and regions to fight for their rights.

श्रमिक आंदोलनों में ट्रेड यूनियनों की स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) देश की सबसे प्रारंभिक और प्रभावशाली ट्रेड यूनियनों में से एक थी। इसने विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों के श्रमिकों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवधि में राष्ट्रीय स्वतंत्रता और श्रम सुधारों की मांग करते हुए कई हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए।

Post-Independence Era and Legislation

After independence, the Indian government enacted various labor laws aimed at protecting workers' rights and improving their working conditions. The Industrial Disputes Act, 1947, and the Minimum Wages Act, 1948, are notable examples. These laws provided a legal framework for addressing labor issues and resolving industrial disputes.

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कार्य स्थितियों को सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न श्रम कानूनों को लागू किया। 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम और 1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उल्लेखनीय उदाहरण हैं। इन कानूनों ने श्रम मुद्दों को संबोधित करने और औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया।

Conclusion

The working-class movements in India have evolved over time, reflecting the changing socio-economic landscape of the country. From the early days of industrialization to the present, these movements have been instrumental in advocating for workers' rights and shaping labor policies. Their continued relevance highlights the ongoing struggle for social and economic justice.

Scholarly Minds

भारत में श्रमिक वर्ग आंदोलनों ने समय के साथ विकास किया है, जो देश के बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान तक, इन आंदोलनों ने श्रमिक अधिकारों की वकालत करने और श्रम नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी निरंतर प्रासंगिकता सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष को उजागर करती है।

TOPIC -3

Introduction to Regionalism in India

Regionalism in India refers to the expression of a regional identity and the desire for recognition and autonomy within the larger framework of the Indian state. It emerges from cultural, ethnic, linguistic, and economic diversities and often influences political and social dynamics in the country.

भारत में क्षेत्रवाद क्षेत्रीय पहचान की अभिव्यक्ति और भारतीय राज्य के बड़े ढांचे के भीतर मान्यता और स्वायत्तता की इच्छा को संदर्भित करता है। यह सांस्कृतिक, जातीय, भाषाई और आर्थिक विविधताओं से उत्पन्न होता है और अक्सर देश की राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है।

Historical Background

The roots of regionalism in India can be traced back to the colonial period when British policies of 'divide and rule' exacerbated regional differences. Post-independence, the reorganization of states based on linguistic lines in 1956 further solidified regional identities.

भारत में क्षेत्रवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई हैं जब ब्रिटिश 'बांटो और राज करो' की नीतियों ने क्षेत्रीय भिन्नताओं को बढ़ा दिया। स्वतंत्रता के बाद, 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्षेत्रीय पहचान को और मजबूत कर गया।

Scholarly Minds

Causes of Regionalism

1. **Cultural and Linguistic Differences:** India is home to a multitude of languages, cultures, and traditions. These differences often lead to a strong sense of regional identity.

   सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नताएँ: भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का घर है। ये भिन्नताएँ अक्सर एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान की ओर ले जाती हैं।

2. **Economic Disparities:** Uneven economic development across different regions can lead to feelings of neglect and demand for greater economic autonomy.

   आर्थिक असमानताएँ: विभिन्न क्षेत्रों में असमान आर्थिक विकास उपेक्षा की भावना और अधिक आर्थिक स्वायत्तता की मांग पैदा कर सकता है।

3. **Political Aspirations:** Regional parties and leaders often capitalize on regional sentiments to gain political power and influence.

   राजनीतिक आकांक्षाएँ: क्षेत्रीय पार्टियाँ और नेता अक्सर राजनीतिक शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का लाभ उठाते हैं।

Conclusion

Regionalism in India is a complex and multifaceted phenomenon. While it can foster a sense of pride and identity among local populations, it also poses significant challenges to national unity and development. Balancing regional aspirations with national interests remains a crucial task for policymakers.

भारत में क्षेत्रवाद एक जटिल और बहुआयामी घटना है। जबकि यह स्थानीय आबादी के बीच गर्व और पहचान की भावना को बढ़ावा दे सकता है, यह राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी पेश करता है।

Scholarly Minds

क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य बना हुआ है।

Scholarly Minds